Seeds Corporation has stopped payment to farmers of East Godavari district in Andhra Pradesh and Tamil Nadu for seeds sold;

(b) whether it is also a fact that the officials of National Seeds Corporation have not met with farmers of East Godavari for two years;

(c) whether these funds have been siphoned away by local agents of National Seeds Corporation; and

(d) the manner in which Government propose to take action in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

दालों के बीजों की नई किस्में

1981. **श्री अजीत जोगी:**

श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दालों के बीजों की विकसित की गई नई किस्मों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख)इन बीजों के प्रयोग से प्रति एकड़ दालों का अनुमानतः कितना उत्पादन प्राप्त किया गया हैं अथवा किये जाने की संभावना हैं; और

(ग)किसानों को उचित मूल्य पर ये बीज मुहैया कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मोहम्मद अयूब खान**) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान 9 मई विकसित/जारी की गई किस्में विवरण में दी गई हैं (**नीचे देखिए**)

(ख)ये नई किस्में संभवतः वर्तमान समय में उगाई जा रही किस्मों की अपेक्षा 10 से 15 प्रतिशत तक अधिक पैदावार देंगी।

(ग)किसानों को बीज उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न बीज संघटकों की सहायता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास प्रयोजना (एन0 पी0 डी0 पी0) के अंतर्गत राज्य कृषि विभाग को आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। इन संघटकों की सूची नीचे दी गई हैं:-

1.	संघटक	सहायता की दर
	प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए बीज ग्रामीण योजना	200.00/-रूपये प्रति क्विंटल
2.	किसानों को प्रमाणित बीज का वितरण।	30.00/-रूपये प्रति क्विंटल
3.	आधारभूत (फाउन्डेशन) बीज का उत्पादन।	40.00/-रूपये प्रति क्विंटल

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दलहनी बीजों की विकसित/जारी की गई नई किस्में

चना	जी एफ 89-36	पूर्वी उत्तर प्रदेश, पं0 बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर पदेश।
	जी एन ज 663	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
	के डब्लू आर 108	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम।

अरहर	क एम-7	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उड़ीसा।
मूंग	एच यू एम-1	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा।
उड़द	बी बी-3	केन्द्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र।
	डब्लू बी यू 108	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक।
मटर	डी एम आर 7	एन डब्लू पी जेड।
मसूर	के एल 133	एन ई पी जेड।

Scheme to Harness Rivers to Control Flood

1982. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to introduce a new scheme under the Eighth Five Year Plan, under which the rivers of the flood affected areas in the country are to be developed in such a manner that the fury of flood comes to an end;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have formulated any scheme to develop certain areas in the country on priority basis during the Eighth Five Year Plan itself; and

(d) if so, the detailed outline of the said scheme and total amount allocated for this purpose, to be spent during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Areas scvcrly affected due to floods in North Bihar have been identified for providing flood proofing measures under a Central Sector Programme. Flood proofing programme involves construction of raised platforms. quick drainage facilities, potable drinking water, sanitary arrangements, education and storage facilities for fodder and other essential commodities. About Rs. 9 crore is expected to be spent for this programme during the 8th Five Year Plan period.

Setting up of Multi-Purposc Cultural Complexes

1983. SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Union Government's proposal for setting up multi-purpose cultural complexes in States has been flopped;

(b) if so, whether several State Governments are not at all interested to set up cultural complexes there;

(c) if so, whether the Union Government itself propose to set up cultural complexes in each State; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.